[Shri Ghulam Rasoo) Matto]

at the present rate of taxation, show a deficit of Rs. 8120 crores and after fresh taxation to Rs. 7484 crores. But the hon. Minister of Revenue and the hon. Minister of Expenditure are here. 1 shall request them that they should assure this country that this Budget deficit will, under no circumstances, be exceeded. If there is any proposal from any Ministry for enhancing grants and allocations, they should be asked why and how they want to make savings in other sectors. This is very important. Under no circumstances should the deficit be allowed to exceed. This must be scrupulously adhered to.

My last point is that our non-Plan expenditure has gone up very high. This is one of the main reasons why they should think in terms of freezing the non-Plan expenditure for the next year. Why should we not think that there should be no increase in the non-Plan expenditure next year? If we can think that there should be no fresh appointments and all that, we can think of freezing the non-Plan expenditure also. When the prices are so escalating, the non-Plan expenditure is bound to increase. So my request to the hon. Minister would bs to consider freezing of non-Plan expenditure. Let us think that for two years we will have an expenditure freeze.

I was not prepared for the speech today. The hon. Minister may kindly consider whatever little observations I have made today and react to them.

THE VICECHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have made out very good points.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): You represent the whole of that side.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : These are the only points I could make today. I was not having the papers with *me* today. I have borrowed from Shri Verma the Budget speech. The Minister may kindly consider the points raised by me and in his reply may react to my suggestions. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

Increase in the Central Issue Prices ofWheat for the Public DistributionSystem and other Schemes

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM); Sir, as the House is aware, the support price of wheat to be paid to the farmer in the coming rabi season was raised by the Government from Rs. 166 to Rs. 173 per quintal. This increase, which was higher than that of the last three years, was widely welcomed.

The Central Government also fixes the price of wheat issued from the Central Pool to th$_s$ State Governments for distribution under the public distribution system and other i related schemes. Consequent upon the Government's decision to increase the support price of wheat by Rs. 7.00 per quintal, the Government hav* decided to refix the Central issue pric«s of wheat to absorb the increase in the support price and some related costs and to contain the food subsidy.

The revised Central issue prices of wheat will be as follows:—

(i) For the public distribution system, it will be Rs. v204 per quintal instead of the existing Rs. 195 per quintal; and

(ii) For the 1TDP areas and tribal majority States, it will be Rs. 139 per quintal against the existing Rs. 130 per quintal and the consumer price will b« Rs. 164 per quintal instead of Rs. 155 per quintal.

The price of wheat for open market sales will be Rs. 240 per quintal.

All these prices will be effective from 25th March, 1988.

6.00 P.M. /

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh); It is most unjustified. >It is nothing but loot.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now, Mr. Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir); Mr. Vice-Chair-main, Sir, I think that the increase of Rs. 9/- per quintal in the public distribution system while only Rs. 7/- has been paid to the farmers is quite unjustified. Last year the farmers were paid Rs. 166/-and the issue price then was Rs. 204/- per quintal and there was an in-built profit of Rs. 38/-. Now, the farmers are not happy because they are not getting their due. But the Civil Supplies Department, in my opinion—the Minister may correct me if I am wrong—got at Rs. 166/- and gave it to the public at Rs. 204|- and they were making a profit of Rs. 38/-.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI); No. The issue price at that time was only Rs. 195/-.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO : AH right. Then they were having a profit of Rs. 29/-. As if that profit was not sufficient and, therefore, he had to raise it by another nine rupees and this has made the confusion worse confounded. Already they were making a profit of Rs. 29/- and now they are making a further profit of Rs. 2/-. I would like the Minister to clarify this and correot me if I am wrong.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRr JAGESH DESAI); Now, Mr. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो घोषणा की है इसके द्वारा जो उपभोक्ता है, जो उत्पादक है, दोनों को लूटने की योजना बनायी गयी है । सरकार ने बराबर इस बात का आश्वासन दिया है इस सदन में और उस सदन में भी कि किसान जो उत्पादक है उनको उनके उत्पादन का रेम्यूनरेटिव प्राइस, लाभप्रद मूल्य दिया जायेगा । जो विवरण प्रस्तुत किया गया है इसमें भी बताया गया है कि पिछले कुछ दिन पहले 7 रुपये की वृद्धि की गयी थी पर-क्विंटल किसान को देने के लिए । आज जो वृद्धि की गई है उसके हिसाब से देखा जाय तो खुले बाजार में गेहूं का भाव 240) रु० होगा, लेकिन सरकार की जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वहां पर आपने 9) रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की है । मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को आप 7) रु० दे रहे हैं और उपभोक्ता से 9) रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं । यह जो आप 2) रु० का लाभ लेना चाहते हैं, यह आप बिचौलियों को क्यों देने जा रहे हैं ? किसानों को आप यह लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं ? जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए ।

आपने इस बात की घोषणा की है कि खुले बाजार में गेहूं का मूल्य 240) रु० प्रति क्विंटल होगा । किसान को तो 173) रु० दे रहे हैं और खुले बाजार में गेहूं 240) रु० में बेच रहे हैं । इस प्रकार 67) रु० आप बिचौलियों को दे रहे हैं । उपभोक्ता से आप ज्यादा दाम लेंगे, किसानों को कम मूल्य देंगे और बिचौलियों को 67) रु० का लाभ देंगे तो इस नीति का समर्थन कौन करेगा ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करें । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि डेटेन्स पर खर्च होगा और दूसरी चीजों पर खर्च होगा । लेकिन आप यह 67) रु० की जो वृद्धि कर रहे हैं, इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसानों को इससे लाभ नहीं होगा । आपकी यह नीति बिलकुल किसान विरोधी है, जन विरोधी है । यह आपकी लाभ की योजना नहीं है, इससे किसानों और गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार से विचार करें कि इसका लाभ किसानों को मिले, गरीब तबके को मिले, जो उपभोक्ता है, जो गेहूं इस्तेमाल करते हैं, उनको इसक लाभ मिलना चाहिए ।

श्री शंकर सिंह वाघेला (गुजरात) : वाइस चेयरमैन साहब, सरकार की जो नीति है वह समर्थन मूल्य देने की है । मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि उनकी इस समर्थन मूल्य वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं । समर्थन मूल्य की जगह इसको प्रोत्साहन मूल्य कहा जाना चाहिए । जो मूल्य आप किसानों को देते हैं, उससे ज्यादा मूल्य उसको बाजार में मिलता है । आप उसको 2) रु० या 5) रु० देते हैं, लेकिन बाजार में उसको ज्यादा दाम मिलते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं का कास्ट आफ प्रोडक्शन सब स्टेट्स में एक जैसा नहीं है । पंजाब और हरियाणा में गेहूं का कास्ट आफ प्रोडक्शन जो है उसके मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात में दूसरा है क्योंकि वहां पर इरीगेशन सोर्सेज उतने नहीं हैं जितने पंजाब और हरियाणा में हैं । सब राज्यों में समर्थन मूल्य आप एक समान देते हैं । आपको हर राज्य की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाल कर देखनी चाहिए और उसी हिसाब से समर्थन मूल्य देने चाहिए । जैसा मैंने कहा, इसको प्रोत्साहन मूल्य कहें तो उचित होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गवर्नमेन्ट कहती है कि यह गरीबों की हिमायती है । गरीबों और ट्राइबल लोगों से वोट मांगने के लिए आप बेशक अच्छी-अच्छी योजनाएं बनाइये, लेकिन इन योजनाओं से इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ... (व्यवधान) । इस टाइम तो गरीबों को मारा जा रहा है । कई राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, कई व्हीट इटर राज्य अकाल से ग्रस्त हैं । आपका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कितना काम कर रहा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । कई इलाकों में अनाज नहीं पहुंच पा रहा है । जिन मजदूरों को 11) रु० पहले मिल जाते थे वे भी अब उनको नहीं मिल पाएंगे । आपको चाहिए था कि आप अकालग्रस्त इलाकों में ज्यादा सुविधाएं देते । आप ट्राइबल और गरीबों के हिमायती कहलाते हैं, आप क्यों नहीं कोई परमानेन्ट व्यवस्था करते हैं जिससे इन गरीबों को रोजगार मिल सके और इन राज्यों को सुविधाएं मिल सकें । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप समर्थन मूल्य के बजाय इसको प्रोत्साहन मूल्य दीजिये । जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है उसको आप प्रत्येक राज्यों में वहां की लागत को देखकर निश्चित कीजिये । जनता पार्टी के समय हमारे गुजरात राज्य में किसानों के लिए भाव बढ़ा दिये गये थे । राज्यों की कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखकर समर्थन मूल्य होना चाहिए । जो बातें मैंने उठाई हैं उनके संबंध में माननीय मंत्री जी कुछ बातें हमें बताएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, we hava^ just heard from the hon. Minister that the issue price for wheat for the coming year has been increased. Now, last year also we had heard from the Minister, a similar statement. But these issue prices are not in consonance with the reality because the production cost is high and they don't get remunerative prices. We may call the prices remunerative. But the price as declared here is not remunerative. Mora-over, the pricing policy of the Government actually helps the monopolist traders. For example, the price of wheat in the open market will be Rs. 240/- per quintal. So, you have declared a price of Rs. 240/- while the market price is already much higher. The Statesman of today states that the wheat dara, kalyan and desi varies cost Rs. 225 to Rs. 250, Rs. 255/-to Rs. 260 and Rs. 270 to Rs. 340 per quintal respectively. Who is going to control the open market? Salary earners, wage earners common people and the peasants who produce foodgrains are being fleeced by these monopoly traders like anything. The Government policy is going to encourage them. There is not a single word about them. Good words are not sufficient. It depends on whether the Government has got an effective distribution system in the tribal areas as well as in other areas. The present distribution system in the rural areas, which is know as 'modified rationing system', is absolutely worthless and ineffective and is in the hands of traders and *arathdars* who are going to control the market. The Government machinery is

not going to control them. But the Government machinery actually helps them.

There is statutory rationing in the urban areas and in the industrial areas. There also there is meagre and bad quality supply of wheat and it helps the traders who fleece the people in the open market. There is no coordination between the Government's declared policy and the ruling prices in the market. In the past also you have increased the support price of wheat. The percentage of increase in the support price of wheat during the last four years, i.e. from 1985-86 to 1988-89, has been surpassed by the issue price that you have declared. So, you have no policy to safeguard the interests of the peasants and the producers. You have no policy to safeguard the interests of the urban consumers. You have no policy to safeguard the interests of the tribals and of the people who are below the poverty line. So, we want from you a definite assurance that you will develop an all-India system of common distribution at a unified price, at a common price. Unless it is done, unless the entire distribution system is taken up by the Government, controlled by it in the interest of the people and you declare *as* price policy which is in the interests of peasants and consumers, there will be no help for the peasants, workers and consumers. Hence the policy declared is merely an eye-wash. It will actually help the monopoly traders and not the peasants and the workers. Therefore, Sir, I request the Government to revise the policy, review it and adopt a popular policy in the interests of the peasantry, in the rests of the workers and in the interests of consumers as well. With these words. Sir, I conclude.

SHRI PRABHAKAR RAO KALVA-EA (Andhra Pradesh): Sir, the Minister has revealed the support price as well as the distribution price but I could not understand how this' support price has been arrived at. The other day the Agriculture Minister declared Rs. 172 per quintal and here the Food and Civil Supplies Minister raises the price of wheat in public distribution system and in the open market. What I feel is that there is no coordination between the two Ministries. The other day we questioned the Agriculture Minister, Mr. Yogendra Makwana how this Rs. 173 per quintal has been arrived at whether the cost of cultivation had been calculated and we asked him about break-up and I want to know the same thing from the Minister of Food and Civil Supplies also. I want to know[1] how he has arrived at Rs. 204 for public distribution system and Rs. 240 for sale in the open market. It seems there are buffer stocks in the country and are you poing *to* operate this scheme for oil released from the buffer stocks? One more point. Under NREP and RLEGP food-grains wheat is given through out the country. I want to know what will be the Government rate for this wheat under NREP and RLEGP.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : किसान जो पैदा करता है उसके उत्पाद का जो मूल्य मिलता है और उसको बेच कर जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है निरन्तर प्रति वर्ष किसान घाटे में जा रहा है। हम लोगों को निरन्तर यह शिकायत है कि किसान को लाभप्रद कीमत नहीं मिलती है । एक तरफ यह शिकायत है कि सात रुपए बढ़ाए हैं जिसे हम लाभप्रद नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ता को 31 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को भी अधिक देना पड़ेगा और किसान को कम कीमत मिलेगी और फिर दो हजार करोड़ रुपया आप सबसिडी का भी बताते हैं खाद्यान्न पर आप सबसिडी और दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी मुझे लगेगा यह शिकायत रही है उपभोक्ता को कौन-सी सबसिडी मिल रही है ? आपने आई० टी० डी० पी० एरिया में और ट्राइबल एरिया मैजोरिटी स्टेट्स को आपने सबसिडी दी है यह समझ आने वाली बात है इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और उन एरियाज में आप 164 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उपभोक्ताओं को देंगे लेकिन किन उपभोक्ताओं को आप 164 रुपए के हिसाब

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

से देंगे यह भी आप बताने की कृपा करें। आई० टी० डी० पी० एरिया में ट्राइबल एरियाज में आपने जो सबसिडी दी है इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं लेकिन शेष देश के उपभोक्ताओं को आपने 31 रूपए फालतू पर दिया । यह जो दो हजार करोड़ रुपए की सबसिडी है जो आप कहते हैं तो क्या यह आपका एफ० सी० आई० का जो इतना बड़ा घाटा है जो उसमें चोरियां होती हैं, भ्रष्टाचार है, जो उसके रख-रखाव में खर्च में गड़बड़ियां हैं क्या सारा का सारा दो हजार करोड़ रुपया एफ० सी० आई० में तो नहीं जा रहा है ? आप प्राइवेट ट्रेड को देखिए मैं प्राइवेट ट्रेड के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एफ० सी० आई० भी उसी तरह से करें जिस तरह से आपकी दूसरी पब्लिक अंडर-टेकिंग्ज कर रही हैं । मैं कल बजट पर बोलूंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके से पब्लिक अंडरटेकिंगज का नुकसान बढ़ रहा है और किस हिसाब से जो टाप के बड़े 20 आदमी हैं वह अपना मुनाफा तेजी से बढ़ाते चले जा रहे हैं ।

मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यह बताने की कृपा करें कि दो हजार करोड़ रुपए की जो सबसिडी आप देते हैं उसे किस प्रकार करेंगे ? 173 में अगर सबसिडीज करते तो समझ में आता कि 150 या 130 में का कंज्यूमर को फायदा पहुंचा । 31 रुपए फालतू लिए तो सबिसिडी कैसे हुई ? फिर आप कंज्यूमर को कैसे 240 रुपए पर । आपने भी बिल्कुल बनिये की दुकान खोल ली । क्या जरूरत थी इस दुकान को खोलने की । अगर फ्लोर मिल को लेना है जिसको 240 पर देंगे तो वे खुले मारकेट से ले सकते हैं, आप क्यों देते हैं ? इसका मतलब यह है कि आप इसमें मुनाफा कमायेंगे । यह आप किसान को दें या उपभोक्ता का लाभ करें ।

तीसरा इसके बीच में चाहे एफ० सी० आई० खाये चाहे गवर्नमेंट खाये यह बीच में मुनाफा खाना सर्वथा निंदनीय है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप बिचोलियों के खिलाफ हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बनिए बन रहे हैं । इसलिए आप बताने की कृपा करें कि किस प्रकार आप उपभोक्ता की सेवा कर रहे हैं और उसको फायदा पहुचा रहे हैं ?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is a welcome measure. The Government has increased the support price for the farmers from Rs. 166 to Rs. 173...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA It was done about 7 months back.

SHRI V. NARAYANASAMY: The features which I find here are, while giving an increase of Rs. 7 to farmers, there is increase of Rs. 9 in the distribution system which has been given *to* ITDP areas and tribal areas. While the price was increased from Rs. 130 to R». 139, and again from Rs. 155 to Rs. 164, I am not able to understand why you are giving only Rs. 7 increase to the farmers. Secondly, I want to know as to what will be the total amount which we are going to get out of this increase in price relating to public distribution system. Thirdly, there is one system which prevails in the country, about which I would like to ask the hon. Minister. And that is about the commission agency system. The Ministry of Food and Civil Supplies, especially the FCI is encouraging private commission agents. In Haryana alone, the Government is giving about Rs. 30 to Rs. 50 cro-Tes to the commission agents. Thus, the Government itself is encouraging private traders, private persons who are dealing in commission agency[1] and this system of commission agents prevails in many other parts of the country.

I would like to know from the hon. Minister as to why the FCI is paying more than Rs. 50 crores to them in Haryana alne. You have got all the paraphernalia of the FCI. I am not able to understand why should you spend so much) money on the commission agents. That money can be very well utilised for the